International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 472-474

संचार उपागम एवं भारतीय राजनीति में प्रासंगिकता

डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना
असि. प्रो., डिपार्टमेन्ट ऑफ पॉलिटकल साइंस, मौलाना आजाद इन्सिटीयूट ऑफ हयूमनटीज, साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

समकालीन राजनीतिक सिद्वांत एवं दर्शन दूसरे अनुशासनों की संदर्भ–परिस्थितियों एवं परिप्रेक्ष्यों से प्रभावित होता है, संचार सिद्धांत इसका एक अच्छा प्रमाण है। इस सिद्धांत का विकास द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय जगत की बढ़ती हुयी परस्पर निर्भरता एवं संबद्धता के कारण किया गया है। संचार सिद्वांत के जनक प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नारबर्ट वीनर है। वीनर महोदय में इस प्रतिमान को विकसित कर ''संचार–नियंत्रण विज्ञान''[1] (Cybernetics Design for a Brain, 1960) की संज्ञा दी। वीनर ने संचार प्रतिमान का विकास संदेश सिद्धान्त (Theory of message), साइबरनेटिक्स (Cybernetics) तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धान्त का विकास किया। वीनर महोदय के अनुसार, ''साइबरनेटिक्स एक ऐसा सिंद्धात एवं तकनीक है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की मशीनें, जीव, मनुष्य, समाज, राष्ट्र एवं राज्य तथा जिस प्रकार से इन समष्टियों के नियंत्रण के लिए संवादों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाता है, का समग्र अध्ययन है।''[2]

राबर्ट सीमार्थ के अनुसार, ''संचार मानव व्यवहार तथा उसके दृष्टिकोणों से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं का गहन अध्ययन है।''[3] ''प्रसिद्ध विद्वान आरेन यंग के अनुसार राजनीतिक संचार एक आधारभूत संरचना है, जिसके माध्यम से राष्ट्र–राज्य की कार्य–प्रणाली का निर्वहन होता है तथा निर्गत व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र–राज्य की नीतियों एवं निर्णयों को समाज के सम्मुख लाया जाता है।''[4]

राजनीतिविज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धान्त को लागू करने का श्रेय हावर्ड के प्रोफेसर कार्ल डायच को है। प्रोफेसर डायच की क्रांति *दि नर्वज ऑफ गवर्नमेंट* (The Nerves of Government) संचार सिद्धान्त की महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में संचार सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त डायच का शोध लेख–*कम्युनिकेशन मॉडेल्स एण्ड डिसीजन सिस्टम* है। यह जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कन्टम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में भी संचार सिद्धांत के शूक्ष्म एवं गहनतम सिद्धांतों एवं प्रवाधियों का उल्लेख प्रो. डायच ने किया है। संचार सिद्धान्त निर्णयों के परिणामों में उतनी रूचि नहीं लेता, जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया में है। शासक अभिजनों का यह रवैया *साइबरनेटिक्स* के प्रतिमान के सिद्धांतों के अनुकूल ही है, क्योंकि उसमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं को दिया जाता है।

कार्ल डायच की भांति स्टीफन वास्वी का मानना है कि, ''यह सिद्धांत जनमत, जनमत निर्माण, मतदान व्यवहार, राजनीतिक विकास, राजनीतिक परिवर्तन या स्थायित्व आदि को प्रभावित करने वाले संचार एवं संचार साधनों के अध्ययन से जुड़ा होता है।''[5] संभवतः इसी कारण राजनीतिक संप्रेषण की समग्रता एवं व्यापकता के कारण इस उपागम को ''राजनीतिक साइबनेटिक्स' (Political Cybernetics) के नाम से जाना जाता है।'' [6]

कार्ल डॉयच संचार सिद्धांत की व्याख्या का आरंभ ही *संचार अभियांत्रिकी* (Communication engineering) और *शक्ति अभियांत्रिकी* में अंतर बताने से करते हैं। डॉयच लिखते है कि शक्ति अभियांन्त्रिकी में परिवर्तन प्रायः उसी अनुपात में होता है, जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। इसके विपरीत, संचार अभियान्त्रिकी में थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी–कभी संदेश के प्राप्तकर्ता की स्थिति में बहुत व्यापक परिवर्तन हो जाता है। ''ऐसी परिवर्तन प्रयोगों में लायी गयी शक्ति के अनुपात में सहस्त्रों गुना बड़े होते हैं।''[7] संचार सिद्धांत का समस्त आधार परिवर्तन है। *परिवर्तन शक्ति* एवं संचार माध्यमों के उपलब्धता के द्वारा होता है, परंतु यह प्राप्त सूचना और उस पर कार्यान्वयन पर निर्भर रहता है। वर्तमान युग में संचार की प्रभाविता के कारण अनेक राज्यों में शासक अभिजनों के निरंकुश रवैये के विरूद्ध विद्रोह हो रहा है। ''इतना ही नहीं, इन राज्यों में नवीन शासक अभिजन पदारूढ़ हो गये।''[8] यह क्रांतिकारी परिवर्तन इन राज्यों में नागरिकों के विक्षोभ को संचार साधनों के व्यापकता के कारण संभव हुआ है।

यह सर्वविदित है कि, संचार सिद्वांत प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय की एक व्यवस्था मानता है। संचार सिद्वांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर आधारित है। प्रथम, वे संकल्पनाएं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है। द्वितीय, वे संकल्पनाएं जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझाना हैं पहले वर्ग में वे संरचनाएं आती हैं, जिन्हे हम स्वागत व्यवस्था की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरा वर्ग, जिसका संबंध सूचना प्रवाहों से है, अधिक महत्वपूर्ण है। ''प्रवाह की इस संकल्पना के साथ अन्य संकल्पनाएं जैसे *चैनल, भार, भारवाहिनी (Load Capacity)* से जुड़ी हुयी है।''[9]

प्रोफेसर डॉयच का मत है कि समूहों और समाजों, राज्यों और अन्तर्राष्ट्रीय समाजों सभी प्रकार के संगठनों की उपादेयता के मापन के लिए संचार शैली की उपयोगिता पर प्रमुखता दिया हैं।''वर्तमान समय में सोशल मीडिया की व्यापकता के कारण शासक अभिजनों के निरकुंश रवैये पर स्वतः प्रतिबंध लगता है।''[10] शासक अभिजन जनकल्याण के लिए नीतियां बनाने पर विवश होते हैं।

यह सर्वविदित है कि, ''डॉयच ने नकारात्मक प्रतिसंभरण (Negative Feedback) को सचांर सिद्धांत की आत्मा माना है''[11] प्रो. डॉयच ने नकारात्मक प्रतिसंभरण को ही संचार सिद्धांत के प्रासंगिकता का आधार माना है। एक अच्छी व्यवस्था की पहचान यही है कि वह सूचना को अविकृत एवं परिमार्जित ढंग से प्राप्त हो सके। प्रो. डॉयच का मत है कि, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही शासक अभिजन अपनी राजनीतिक संरचना को जनहितकारी एवं सर्वसुलभ बना कर अपने शासन व्यवस्था को चिर स्थायी बनाते है। जैसे–वर्तमान के लोकतांत्रिक परिवेश की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता के कारण ही भूटान नरेश ने अपनी निरंकुश शक्तियां संसद को सौप कर स्वयं संवैधानिक शासक बन कर लोकतंत्र के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

डॉयच ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण में चार परिणात्मक तत्वों को जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। ये चार तत्व क्रमशः है– भार (Load), पश्चता (Lag), अभिलाभ (Gain) और अग्रता (Lead)। भार का अर्थ परिवर्तनों की उस व्यापकता ओर गति से है , जो लक्ष्योन्मुखी हो। पश्चात का अर्थ निर्णयों और कार्यो के परिणाम से है। अधिलाभ

का अर्थ प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक और प्रभावशाली होगा। अग्रता का अर्थ है कि, सुचारू कार्यवाही का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

यह सर्वविदित है कि ''संचार सिद्धांत के कारण विश्व में *प्रवीणता क्रांति* (Skilled Revolution) का प्रसार हो रहा है।''[12] यह क्रांति शासक अभिजनों को जनोन्मुखी एवं उत्तरदायी बना रही है। इतना ही नहीं, आज अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन तथा दबाव समूह सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो पर बहस द्वारा आम जनता को जागृत कर रही है। ''यह उपागम प्राकृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के मध्य सेतु निर्मित करने पर बल देता है''।[13] राजनीतिक परिदृश्य को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए प्लेटो, जॉन ऑफ सेल्सबरी, हॉब्स, रूसों और हर्बट स्पेन्सर जैसे दार्शनिकों ने अपने–अपने ढ़ग से परिभाषित किया है। वर्तमान समय में डॉयच जैसे विद्वनों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की यांत्रिकता को दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया है।

संचार–सिद्धांत के संबन्ध में डॉयच द्वारा प्रतिपादित संकल्पनाओं की सूची यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ''डॉयच ने अधिगम, नवीनीकरण (innovation), संवृद्धि और आत्मरूपांतरण की संकल्पनाओं का भी प्रयोग किया जाता है''।[14] अधिगम कार्य करने की दक्षता को प्रदर्शित करता है। प्रो0 डॉयच ने ऐसे उदाहरण दिये है, जिनमे शासक अभिजनों द्वारा जनता के समक्ष लोकप्रिय चुनावी

वायदे किये जाते है और ये वायदे अधूरे ही रहते है। जनमानस में शासक अभिजनों के प्रति विक्षोभ उत्पन्न होता है और शासक अभिजन सटीक सूचनाओं के माध्यम से विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं, जिनसे जनता की नाराजगी को दूर किया जा सके। संचार सिद्धांत की इसी सार्थकता के कारण प्रसिद्ध विद्धान ओरन यंग का मत है कि, ''यह सिद्धांत सकारात्मक विश्लेषण की दिशा में अत्यंत प्रभावशाली उपागम है''।[15] उपयुक्त फीड़बैक के माध्यम से ''शासक अभिजन अपनी सत्ता बचाये रखने के लिए जनहितकारी नियमों को बनाने के लिए बाध्य होते हैं, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे।''[16] गुजरात विधान सभा चुनाव प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह सर्वविदित है कि, गुजरात विधान सभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा गुजरात प्रान्त के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा कर गुजरात की जनता की सत्ता के प्रति तत्कालिक रोष को मंद किया गया। इतना ही नहीं, भारत में भी पिछले कुछ वर्षो से 'सोशल मीडिया' ने भारत में 'गेम–चेंजर' की तरह काम किया है। राजनीति, व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में 'सोशल मीडिया' ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई है। जिस 'मोदी लहर' की मीड़िया वाले आए–दिन अपनी 'न्यूज–डिबेट' में चर्चा करते हैं, उस लहर को आक्रामक बनाने में 'सोशल मीडिया' की अहम भूमिका है।

वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य एवं आकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद केवल फेसबुक पर 29 मीलियन लोगों ने 227 मिलियन बार, चुनाव से सम्बन्धित पारस्परिक क्रियाएं (जैसे पोस्ट लाइक, कमेंट, शेयर इत्यादि) की। इसके अतिरिक्त 13 मिलियन लोगों ने 75 मिलियन बार केवल नरेन्द्र मोदी के बारे में बातचीत की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 814 मिलियन योग्य मतदाताओं वाले देश (भारत) में सोशल मीडिया का प्रचार का पैमाना लोकसभा चुनावों के दौरान व्यापक था।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता में एकजुटता की नयी प्रवृत्ति देखी गयी है। समायिक मुद्दो पर जनमत निर्माण करने का कार्य भी सोशल मीड़िया के द्वारा किया जाता है। सोशल मीड़िया का यह कार्यात्मक स्वरूप वैश्विक है। भारत में अनेक जन उभारों में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल कानून के लिए किये गये सफल आंदोलन की सफलता में संचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका है। संचार माध्यमों के उपलब्धता के कारण ही जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हुयी और अन्ना हजारे को समर्थन देकर आंदोलन को जीवंत कर दिया गया। संचार माध्यमों की सशक्त भूमिका के कारण ही विद्धानों द्वारा प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध एवं जनलोकपाल के लिए चलाये गये आन्दोलन को ''नई राजनीति''[17] की संज्ञा दी गयी है।

यह सर्वविदित है कि, संचार प्रौद्योगिक ने जनहितार्थ *''आंगुलिक लोकतंत्र''*[18] (Digital Democracy) के माध्यम से नागरिक एवं सरकार दोनों को लाभान्वित किया है। संचार–प्रणाली ने कल्याणकारी राज्य के आदर्श को पूरा करने के लिए ई–गवर्नेन्स की अवधारणा पर बल दिया है। शासक अभिजनों द्वारा ई–गवर्नेन्स का प्रयोग कर प्रशासन को सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी बनाया जा रहा है। आज संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग से जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है, जैसे सूचना का अधिकार। ''यह कानून एक मूलभूत मानव अधिकार है, जो आम जनता की गरिमा बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है''।[19] यह कानून अन्य सभी मानवाधिकार व्यवस्थाओं का सार है, क्योंकि यह नागरिकों को अन्य अधिकारों के प्रति अर्थपूर्ण बनाता है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र एवं विकास की आधारशिला है। संचार–अधिगम के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली तात्विक एवं पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना करती है। भारत में सूचना के अधिकार के माध्यम से गरीबी निवारण, न्यायसंगत, आर्थिक सवंृद्धि से सम्पन्न राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अंततः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त हम कह सकते है कि, संचार पद्धति के विकास के कारण शासन में पारदर्शिता एवं आम जनता राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुयी है। इतना ही नहीं, समकालीन युग में संचार उपागम के विकास के कारण हाशिए पर स्थित जनसमूह भी लाभान्वित हुयी है। आज भारतीय ही नहीं, वैश्विक दृष्टिकोण से Post truth या सत्यातीत युग है। इस युग में संचार भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गयी है। आज युवा, वंचित, महिलाए, दलित, अल्पसंख्यक अपने हितों के रक्षार्थ एवं आपसी एकजुटता के लिए संचार उपागम की मुख्य भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये समूह स्वतः स्फूर्त ढंग से शासक अभिजनों के दमनकारी रवैये का विरोध भी कर रहे हैं। वंचित वर्गो का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रवैया जीवंत भारतीय लोकतंत्र एवं संचार साधनों की सार्थकता को प्रदर्शित करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वर्मा, एस.एल. :उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, नेशनल पब्लिसिंग हाऊस, जयपुर, वर्ष 2002, पृष्ठ 348।
2. वीनर, नारवर्ट : दी ह्यूमन यूसेज ऑफ ह्यूमन वीइंगः साइबरनेटिक्स एण्ड सोसाइटी, ह्यूमन मिक्लिन, वोस्टन, वर्ष 1954, पृष्ठ, 15
3. नार्थ, रावर्ट सी : दी ऐनीलिटिकल प्रोसेस ऑफ कम्यूनीकेशन थ्योरी, फ्री प्रेस, वर्ष 1967 , पृष्ठ 305
4. यंग, ऑरेन आर : सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल साइंस, न्यूजर्सी, प्रिटिंस हॉल, वर्ष 1968, पृष्ठ 52
5. वास्वी, स्टीफन एल : पॉलिटिकल साइंस (दी डिसीप्लीन एण्ड इट्स डायमेनसंस), कलकत्ता, साइंटिफिक बुक एजेंसी, वर्ष 1970, पृष्ठ 142
6. जौहरी, जेसी : तुलनात्मक राजनीति, स्ट्रलिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लि., नई दिल्ली, पृष्ठ 171
7. घई, यू.आर. : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार, न्यू एकेडमी पब्लिसिंग हाउस, जालांधर, वर्ष 2005, पृष्ठ 107
8. सिंह, रवि प्रताप : रजनी कोठारी राजनीतिक चिंतन, साहित्य संस्थान, गाजियाबाद, वर्ष 2016, पृष्ठ 223
9. फाड़िया, बी.एल. : अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2005, पृष्ठ 76
10. शर्मा, एल.एन. कृष्ण मुरारी : राजनीतिक समाजशास्त्र, ओरियंट, ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, वर्ष वर्ष 2014, पृष्ठ 267
11. वर्मा, एस.सी. : आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, वर्ष 1998, पृष्ठ 275

12. बरमानी, आर.सी. : समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध, गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, वर्ष 2007, पृष्ठ 9
13. जौहरी, जे.सी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा राजनीति, स्टर्लिंग पब्लिसर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, वर्ष 2011, पृष्ठ 113
14. गेना, सी.बी. : तुलनात्मक राजनीति, विकास, पब्लिसिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, वर्ष 2005, पृष्ठ 442
15. यंग ओरन आर : सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल साइंस, न्यजर्सी, प्रेंटिस हॉल, पृष्ठ 56
16. विस्वाल, तपन : तुलनात्मक राजनीति (संस्थाए और प्रक्रियाएं), ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ 31
17. यादव, योगेन्द्र : दि न्यू पॉलिटिक्स नामक लेख दैनिक समाचार पत्र, दि इंडियन एक्सप्रेस में 2 जनवरी वर्ष 2013 को प्रकाशित।
18. दुबे, अशोक कुमार : 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैग्राहिल, नई दिल्ली, वर्ष 2008, पृष्ठ 189
19. सिंह, अभय प्रसादः समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृष्ठ 411